sive postal cards, inland letters, envelopes and forms of different kinds;

(b) which are the printing presses used for the purpose with the break-up of percentage of total printing;

(c) whether Government are satisfied with the productivity of its own postal printing press;

(d) if so, whether more work of printing postal forms is proposed to be allotted to the existing postal printing press; and

(e) whether Government are proposing to go for the expansion of the existing printing press?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The total amount spent on printing of forms is Rs. 17.71 crores average for last three financial years. Information regarding the total amount spent annually for printing of postage stamps, post cards, inland letters and envelopes is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) The Department utilises the Government of India Presses (at Aligarh, Koraty, Nasik and Santragachi, Calcutta)t as well as the departmental lPress at Bhubneshwar and printing of forms is also undertaken by the Heads of Postal Circles through private presses.

The approximate percentage of printing done by the three types of presses is indicated below:—

Government of India Press	50%
Department Press	7%
Private Presses	43 %

The postage stamps, post cards, inland letters, cards and envolpes are being printed at India Security Press, Nashik and Security Printing Press, Hyderabad. Information regarding the break-up of the percentage of printing between the two presses is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) Efforts are on to increase the productivity.

(d) Yes, Sir. More work is proposed to be allotted to the postal printing Press at Bhubaneshwar after expansion of its capacity.

(e) Yes, Sir.

बृहत् नेपाल का प्रस्ताव

1488. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1991 के "स्टेटसमैन' में सेन्टर टेक्स सीरियम नोट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने कतिपय स्वार्थी तत्वों की देश के कतिपय भाग को मिलाकर एक बृहत् नेपाल बनाये जाने की मांग की ओर ध्यान दिया है ;

(ग) क्या सरकार इस मांग को उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए अरुचिकर और हानिकर सिद्ध करने के लिए विकास कार्य शुरू करने तथा कतिपय अन्य ठोस कदम उठाने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ङ) सरकार को समाचार की जानकारी है। सरकार को इस प्रकार की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सरकार किसी भी स्त्रोत से की जाने वाली इस प्रकार की मांगों को नहीं मानती है । जी०एन० एल० एफ० के साथ हुए समझौते के अनुसार क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास और गोरखाओं और दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अन्य समुदायों के सांस्कृतिक विकास के लिये एक स्वतशासी दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद का गठन किया गया है।